

# पहल

ई—समाचार पत्र (मासिक) – सत्तरवां संस्करण (माह अगस्त, 2022)

→ “पहल” के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. ग्राम पंचायत कोदसा मे गोबरधन परियोजना
3. जिला मंडला में बालमित्र पंचायत हेतु “एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम” अन्तर्गत “स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र”
4. आजीविका मिशन बदली सोनकली की जिन्दगी
5. स्व—सहायता समूह भी कर रहे है मुनगे की नर्सरी तैयार
6. आपदा के प्रकार – ज्वालामुखी
7. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मेसन प्रशिक्षण वर्ष 2022
8. महिला राजमिस्त्री की सफलता की कहानी
9. समूह से मिला रोजगार और बनी पहचान – सफलता की कहानी
10. जल की प्रचुरता वाला गांव



## प्रकाशन समिति

### संरक्षक एवं सलाहकार

श्री उमाकांत उमराव (IAS)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

### प्रधान संपादक

श्री संजय कुमार सराफ,

संचालक,

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास

एवं पंचायतराज संस्थान—म.प्र., जबलपुर

### सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,

उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.—म.प्र., जबलपुर



ई—न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें—mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : [www.mgsird.org](http://www.mgsird.org), Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR





## अपनी बात...



“पहल” मासिक ई-न्यूज लेटर का सत्तरवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का छठवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में संस्थान में “स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी अमृत महोत्सव” पर संचालक, श्री संजय कुमार सराफ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर संस्थान के अधिकारीगण, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर एवं शासकीय सेवक शामिल हुये, जिसे समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

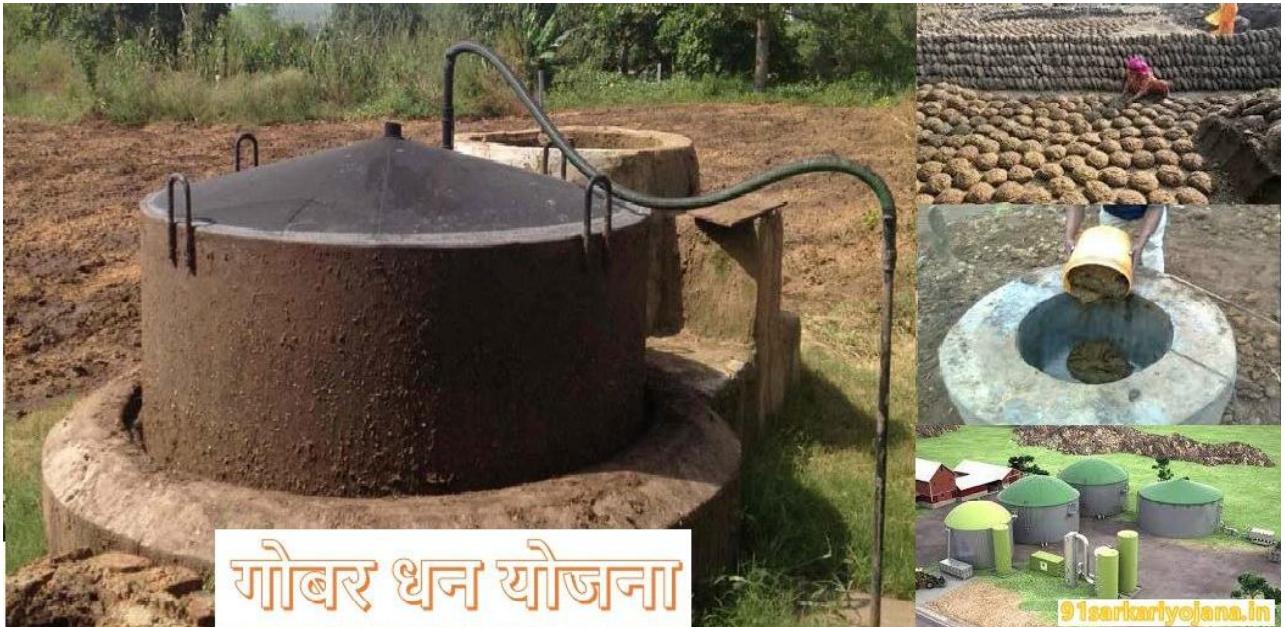
इससे साथ ही “ग्राम पंचायत कोदसा मे गोबरधन परियोजना”, “जिला मंडला में बालमित्र पंचायत हेतु ‘एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम’ अन्तर्गत ‘स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र’”, “आजीविका मिशन बदली सोनकली की जिन्दगी”, “स्व-सहायता समूह भी कर रहे है मुनगे की नर्सरी तैयार”, “आपदा के प्रकार – ज्वालामुखी”, “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मेसन प्रशिक्षण वर्ष 2022”, “महिला राजमिस्त्री की सफलता की कहानी”, “समूह से मिला रोजगार और बनी पहचान – सफलता की कहानी” एवं “जल की प्रचुरता वाला गांव” आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ‘पहल’ का यह संस्करण आपको अत्यंत रुचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ  
संचालक



## ग्राम पंचायत कोदसा मे गोबरधन परियोजना



### गोबर धन योजना

जिला नरसिंहपुर की दूरी जबलपुर से 90 कि.मी. है। यह स्टेट हाईवे 22 पर स्थित है, इसकी भोपाल से दूरी 251.8 कि.मी. है। जिला नरसिंहपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए गए हैं। जिला नरसिंहपुर को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।

जिला नरसिंहपुर के जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत कोदसा मे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गोबरधन परियोजना से गोबर गैस संयंत्र लगाया गया है। ग्राम पंचायत कोदसा मे गोबरधन परियोजना द्वारा ग्राम मे स्थित गौशाला से गोबर खरीदकर गोबर गैस संयंत्र के अंदर घोल तैयार कर डाला जाता है, जिससे इस संयंत्र से गैस तैयार होती है। जिसे एक ओर तो ग्राम पंचायत के निवासियों को गैस की सप्लाई होती है।

### गोबरधन परियोजना ग्राम पंचायत कोदसा



वही दूसरी ओर गौशाला को भी पशुओं की देखभाल के लिए आमदनी हो जाती है। जिससे ग्राम पंचायत निवासियों को अक्षय उर्जा स्रोत से घरेलू कार्य हेतु यानि खाना बनाने हेतु गैस आसानी से उपलब्ध हो रही है। इस अभिनव प्रयोग से



हमारे ग्राम वासियों की घरेलू गैस सिलेन्डर पर निर्भरता कम होगी। एक ओर हमें गैस कम दर पर उपलब्ध होगी वही हमारे देश को कूड़ आयल खरीदने के लिए डालर नहीं खर्च करने पड़ेगे। इसका स्वीकृत माडल है



सी बल्क जनरेटर, इस माडल की प्लांट क्षमता  $45 \text{ m}^3$  है। इसके लिए आवश्यक सामग्री गोबर 1500 किग्रा है। जिससे ग्राम पंचायत के 16 निवासरत परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना की लागत 12,56 लाख रु है। जिसमें हितग्राही अंशदान 50 प्रतिशत है। इस संयंत्र के संथापित होने से ग्रामीण परिवारों को गाँव के अंदर ही गैस की सप्लाई मिल जाने से कहीं बाहर लकड़ी बीनने या गैस के सिलेन्डर हेतु जाना नहीं पड़ता है।

साथ ही गैस की अनवरत सप्लाई से गैस खत्म होने की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ गोबर 2 रु किलो खरीदा जाता है और उससे घरेलू गैस तैयार कर घरों में सप्लाई किया जाता है। इस गैस के दाम घरेलू गैस सिलेन्डर से भी कम है, जिससे ग्रामीण जन के जीवन में हर्ष और उल्लास है।

अभिषेक नागवंशी  
संकाय सदस्य



## जिला मंडला में बालमित्र पंचायत हेतु “एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम” अन्तर्गत<sup>“स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र”</sup>

बचपन एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा साथ, प्यार और दुलार की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाल्यवस्था में बच्चों का मन कोमल होता है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में बच्चों के साथ शोषण की कई घटनाएं सामने आती हैं। यह शोषण आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी होता है। हालांकि कोमल मन होने के कारण बच्चे इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों के शोषण पर लगाम लगाने के लिए बाल अधिकार कानून सामने लाया गया।



प्रदेश के आदिवासी समुदाय बाहुल्य जिला मंडला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन के अभिसरण से “एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम” परियोजना के अन्तर्गत स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन एवं विभिन्न बाल मित्र गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण भारत शासन के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस दिशा में जिला मंडला की पंचायतें “बालमित्र पंचायत” की थीम पर विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहीं हैं जिसमें सबसे प्रमुख “स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र” बनाया जाना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना मंडला में जिला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह के संरक्षण, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से चिन्हित ग्राम पंचायतों में “स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र” बनाये जा रहे हैं। जिले की चिन्हित की गई ग्राम पंचायतों में पहले से संचालित आगंनवाड़ी केन्द्रों का कायाकल्प शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र एक ऐसी अभिनव संकल्पना है जिसमें शासन एवं पंचायत पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आता है अर्थात यह “शूल्य लागत” गतिविधि जो जन-सहभागिता से स्व-संचालित होती है। इसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद (एडाप्ट) लिया जाता है। जो व्यक्ति आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लेते हैं उनके विशेष सहयोग व सहभागिता से आगंनवाड़ी केन्द्र में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं।



## अडॉप्ट आंगनवाड़ी केन्द्र-ग्राम कोंड्रा (बैगा टोला)

मंडला जिला में बिनेका ग्राम पंचायत अंतर्गत विशेष आदिम जाति बैगा बहुल ग्राम कोंड्रा को स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत जिला मंडला की कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने ग्राम कोंड्रा आंगनवाड़ी केंद्र को गोद (एडाप्ट) लिया है।

यह आंगनवाड़ी स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित की गई है।

इस आंगनवाड़ी केंद्र में कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह के पिता श्री अनिल सिंह का जन्म दिन केक काट कर मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर और उनके माता-पिता ने बच्चों को बैग, स्लेट, पाठ्यसामग्री, पानी की बोतल, थाली, चम्मच, गिलास भेंट किया।

आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए मनोरंजन खिलौने, चित्रकला तथा टेबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चे खेल-खेल में मनोरंजनपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर परिसर में कलेक्टर एवं अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया।

### एडॉप्ट आंगनवाड़ी केन्द्र-नैज़रटोला

महिला एवं बाल विकास परियोजना बीजाडांडी के पर्यवेक्षक सेक्टर बीजाडांडी कं. 1 के अन्तर्गत आगंनवाड़ी केन्द्र नैज़रटोला को श्रीमती शारदा ठाकुर द्वारा अडॉप्ट किया गया है। श्रीमती ठाकुर द्वारा स्वयं आगंनवाड़ी केन्द्र में आकर्षक पैटिंग की गई है। जिससे आगंनवाड़ी केन्द्र काफी आकर्षक दिखने लगा है। जनसहयोग से बच्चों के लिये कार्यकर्ता द्वारा खिलौने एकत्रित किये गये हैं। इनका उपयोग बच्चों द्वारा बहुत उत्साह और उमंग से किया जा रहा है। इस केन्द्र में जनसहयोग से किचिन गार्डन, पोषण मटका तैयार किया गया है।



## एडॉप्ट आंगनवाड़ी केन्द्र-कटंगी

महिला एवं बाल विकास परियोजना बीजाडांडी के पर्यवेक्षक सेक्टर पौडी नगरार के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र कटंगी को श्री चंद्रकांत बडगौया द्वारा बच्चों के बैठने के लिये कुर्सियाँ प्रदान की गई। जनसहयोग से बच्चों के लिये कार्यकर्त्ता द्वारा खिलौने एकत्रित किये गये हैं। जिनका बच्चों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।



जनसहयोग से पोषण मटका हेतु सामग्री एकत्रित की गई। जिसका उपयोग बाल भोज में किया जा रहा है। महिलाओं का सहयोग लेकर खाली बैग से बच्चों के लिये खिलौने तैयार किये जा रहे हैं। समुदाय द्वारा समय-समय पर स्थानीय फल जैसे पपीता, अमरुद आदि का माह में एक या दो बार बच्चों के लिये वितरण किया जाता है।

## स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु निरंतर प्रयास

स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र राजीव कॉलोनी मण्डला एवं कोंड़ा (बैगाटोला) को जिले की कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने गोद लिया है तो वहीं जिला पंचायत मंडला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रानी बाटड द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत द्वारा शांति नगर आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री शरद बिसैन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र बढार एवं पीआईयू विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री जी पी पटले द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र बिलगांव को गोद लिया गया है।

इसी प्रकार श्री कमलकांत सोनी, व्यवसायी द्वारा ग्राम आमानाला, श्री जयदत्त झा, समाजसेवी द्वारा ग्राम चटुआमार, आगाज युवा संस्थान द्वारा ग्राम देवदरा, श्री मुकेश कुमार मरावी, व्यवसायी द्वारा ग्राम बड़ोला के आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लिया गया है। जनसहभागिता से स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिये जाने का सिलसिला अब आगे बढ़ता ही जा रहा है।



## जनसहभागिता, अभिसरण, अनुकरण

कलेक्टर श्रीमती हर्षिता सिंह द्वारा बताया गया कि स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की टीम, चित्रकार, विभागीय अमला, नागरिकों का विशेष सहयोग मिल रहा है। जिला मंडला में स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने के लिये किये जा रहे विशेष प्रयासों से निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। इसी प्रकार के प्रयासों का अनुकरण अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।



डॉ. संजय कुमार राजपूत  
संकाय सदस्य



## आजीविका मिशन बदली सोनकली की जिन्दगी



राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलाओं की दिशा एवं दशा बदलने एवं जेण्डर असमानता को समाप्त करने में महती भूमिका निभा रहा है।

महिलायें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) के अन्तर्गत ग्राम में स्व सहायता समूह गठित कर अपने हिसाब से सुलभ तरीके से बैंकों से ऋण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं एवं अपने छोटे से व्यवसाय को बढ़ा रही हैं महिलायें आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर संबल हो रही हैं।

जिला सिवनी के जनपद पंचायत घंसौर के ग्राम कुसमी निवासी सोनकली भगदिया का कहना है कि परिवार मजदूरी कर अपना गुजर बसर कर रही थी जिसके चलते आर्थिक परेशानियां हमेशा बनी रहती थीं, इसी दौरान आजीविका मिशन बनी रहती थी, इसी दौरान आजीविका मिशन द्वारा सोनकली को सूरजमुखी आजीविका स्व सहायता समूह में शामिल किया गया।

सोनकली ने ग्राम संगठन से 50000 / पचास हजार ऋण लेकर मिक्सर मशीन ली जिसे सोनकली के पति ने अपना कार्य प्रारम्भ किया जिससे माह में परिवार को 10 से 12 हजार रुपये मासिक आय होने लगी। सोनकली ने ग्राम संगठन को समय पर पूरा ऋण चुका दिया। सोनकली ने पुनः सी सी एल से 50000 /- ऋण लेकर सेटिंग का समान खरीदा एवं

भवन निर्माण में किराये से देना प्रारम्भ किया आज सोनकली को मिक्सर मशीन एवं सेटिंग से 15 से 18000/- मासिक आय प्राप्त हो रही है वर्तमान में सोनकली का पूरा परिवार रोजगार कर रहा है गांव में ही काम करके राशि कमाना सोनकली के परिवार का कार्य एवं आमदनी से बहुत खुश है इसका पूरा श्रेय राज्य ग्रामीण अजीविका मिशने को है।

सी.के. चौबे,  
संकाय सदस्य

### संस्थान में स्वतंत्रता दिवस भारत अमृत महोत्सव कार्यक्रम



संस्थान में स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी अमृत महोत्सव पर संचालक, श्री संजय कुमार सराफ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर संस्थान के अधिकारीगण, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर एवं शासकीय सेवक शामिल हुये।



## स्व-सहायता समूह भी कर रहे हैं मुनगे की नर्सरी तैयार

आजीविका मिशन विकास खण्ड शाहगढ़ के ग्राम हनुमानटौरा में श्री गणेश स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा मुनगा की नर्सरी तैयार की जा रही है इस मुनगा उत्पादन का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से दूर करना है सामान्यतः मुनगा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन एंव विटामिन्स पाया जाता है अब तक श्री गणेश स्वसहायता समूह द्वारा 400 पौधे 10 समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किये गये हैं मुख्य रूप से स्वसहायता समूह अध्यक्ष जयोति पटेल व सचिव रामरति पटेल द्वारा विशेष रूप इस नर्सरी को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

आजीविका मिशन शाहगढ़ में अभी जून माह से लेकर जुलाई माह तक विभिन्न ग्रामों में मुनगो की



नर्सरी का कार्य होगा आजीविका मिशन विकास खण्ड शाहगढ़ नर्सरी का कार्य अनूप तिवारी जिला परियोजना प्रबेधक एवं विकास खण्ड सहायक प्रबंधक अम्बिका ठाकुर के मार्ग दर्शन मे हो रहा है।

चूंकि मुनगे की खेती में लोगों का रुझान धीरे धीरे कम हो गया है और ग्रामीण मुनगे का महत्व न समझ रखने के कारण ग्रामों में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं इसलिए सरकार विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से मनगे के वृक्षा रोपण करने हेतु जोर दे रही है ताकि ग्रामों में महिलाएं, बच्चे एवं अन्य में पोषक तत्व की कमी न हो और मातृ मत्यु दर एवं शिशु मत्यु दर को कम किया जा सके और गांव में जिन बच्चों का बजन अत्यंत न्यून होता है उनकी न्यूनता का खत्म किया जा सके।



लवली मिश्रा  
संकाय सदस्य



## आपदा के प्रकार – ज्वालामुखी



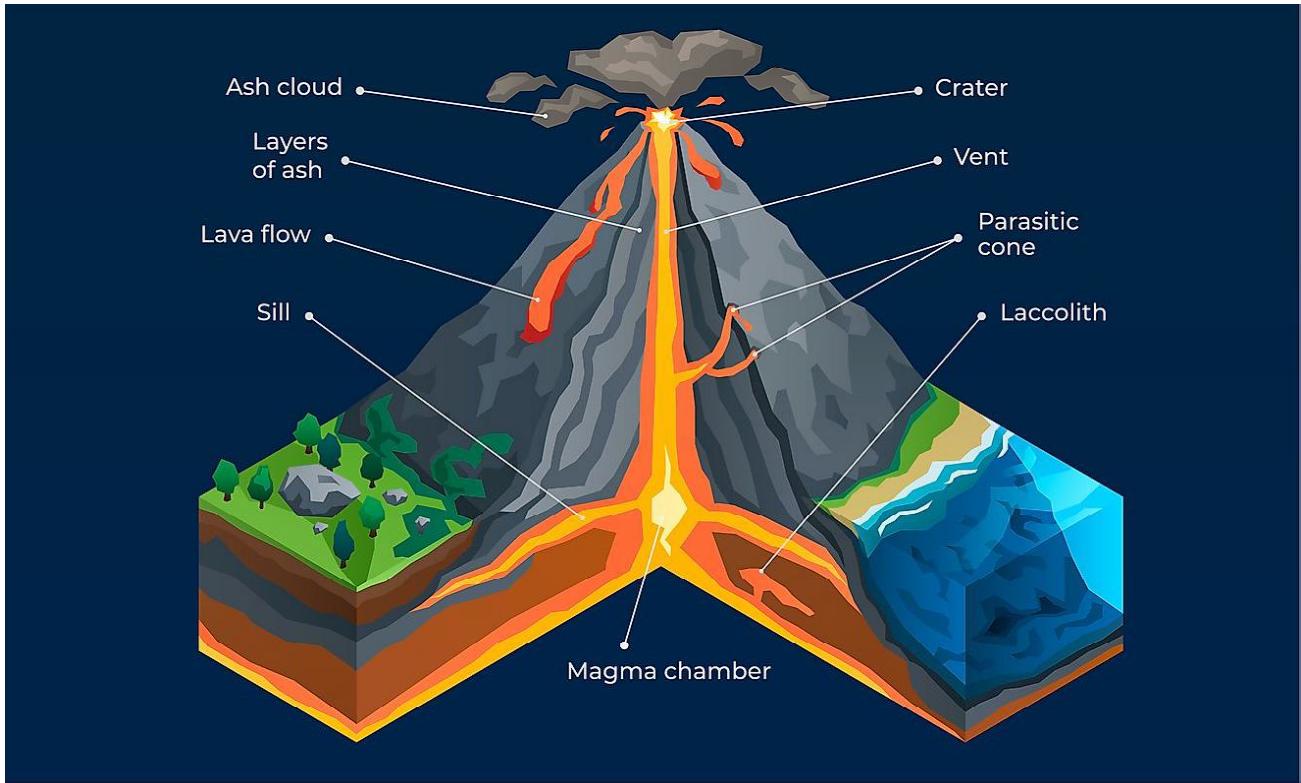
### ज्वालामुखी क्या है?

ज्वालामुखी पृथ्वी की पर्फटी में एक छिद्र होता है जिससे पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित मैग्मा चैम्बर से गर्म लावा गैसे चट्टाने ज्वालामुखीय राख और भाप बाहर निकलते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों को जिनमें नियमित रूप से विस्फोट होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें अतीत में तो विस्फोट हुआ था किन्तु वर्तमान में वे शांत हैं। जिन ज्वालामुखियों में बेहद लम्बे समय में विस्फोट नहीं हुआ है, उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है।

### भारत के ज्वालामुखियों की सूची

क्रमांक	ज्वालामुखी का नाम	राज्य
1.	बैरन द्वीप (सक्रिय)	अंडमान द्वीप समूह
2.	नारकोडम (विलुप्त)	अंडमान द्वीप समूह
3.	बारातांग (विलुप्त)	अंडमान द्वीप समूह
4.	दक्कन ट्रैप (विलुप्त)	महाराष्ट्र
5.	धिनोधर पहाड़ी (विलुप्त)	गुजरात
6.	धोनी पहाड़ी (विलुप्त)	हरियाणा





## ज्वालामुखी विस्फोट के कारण

ज्वालामुखी विस्फोट मुख्य रूप से कंपन गतिविधियों या दुर्बलता वाले क्षेत्रों में होते हैं, उदाहरण के लिए, जहां पृथकी की महाद्वीपीय प्लेटे एक –दूसरे से दूर हटती हैं या टकराती है। यह वहां भी घटित होता है जहां पृथकी की परत निरंतर पिघल रही होती है।

## भारत में ज्वालामुखी जोखिम

भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। इसने 150 से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद वर्ष 1991 में गतिविधि प्रदर्शित करनी प्रारम्भ की थी। जनवरी 2017 में इसने एक बार फिर से राख उगलना आरंभ कर दिया है। यह ज्वालामुखी द्वीप निर्जन है तथा इस द्वीप का उत्तरी हिस्सा बंजर और वनस्पति रहित है।

**डॉ. त्रिलोचन सिंह,  
संकाय सदस्य**



## प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मेसन प्रशिक्षण वर्ष 2022



“सबके लिए आवास” वर्ष 2024 तक भारत के सभी आवासहीन एवं वंचित वर्ग के ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवम्बर 2016 को आरंभ की गई। शासन की मंशा केवल आवास निर्माण नहीं अपितु गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण पर केन्द्रित होने के कारण आवास निर्माण हेतु कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता भी एक आवश्यक घटक है। जिस हेतु वर्ष 2022–23 में म.प्र. में 10000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उक्त घटक के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन द्वारा राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवास निर्माण हेतु कुशल राजमिस्त्री उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी क्षमताओं की वृद्धि कर उनके आजीविका साधन की वृद्धि एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया एवं इस हेतु “राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद” (CSDCI) नई दिल्ली एवं मैनेजमेंट एण्ड इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल (MEPSC) नई दिल्ली द्वारा लीड ट्रेनर्स का प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। इस हेतु लीड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग CSDCI & MEPSC नई दिल्ली के विशेषज्ञों के द्वारा संस्थान में दिनांक 18 से 24 जुलाई 2022 तक सम्पन्न कराई गयी, इस प्रशिक्षण में कुल 22 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,  
संकाय सदस्य



## महिला राजमिस्त्री की सफलता की कहानी



प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण (पीएमएवाय—जी) के अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण में पांचवे चरण में जिला बैतूल के अंतर्गत आने वाले 10 जनपद पंचायतों में 182 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अंतर्गत गठित स्व—सहायता समूह की दीदीओं को राजमिस्त्री के प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाकर राजमिस्त्री प्रशिक्षण का पांचवा चरण माह 2019 में प्रारम्भ करना था।

राजमिस्त्री का कार्य अभी तक ऐसा माना जाता है कि केवल पुरुष कर सकते हैं। महिला नहीं इस लैंगिक भेदभाव को महिलाओं ने समाप्त कर 182 महिलाओं राजमिस्त्री का 45 दिनोंका प्रशिक्षण मॉड्यूल आवास (पीएमएवाय—जी) में राजमिस्त्री का कार्य सीखकर पूर्ण किया इस की परीक्षा सीएसडीसीआई दिल्ली द्वारा स्कील इंडिया के अंतर्गत हुई एवं प्रमाण पत्र भी दिये गये। सवाल उठता है कि समाज में महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण के पूर्व कौन—कौन सी परिस्थिति ताने बाने एवं समाज की नकारात्मक दृष्टि से गुजरना एवं प्रशिक्षण के दौरान पुरुषों के साथ काम करने में क्या कठिनाईयां आई। राजमिस्त्री महिलाओं लैंगिक भेदभाव (जेंडर समस्या) को समाप्त करने का प्रयास किया गया। निश्चित ही महिला चाहे तो समाज में चली आर हीं जेंडर अर्थात् लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सकती है।

जनपद पंचायत मुलताई जिला बैतूल में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु राजमिस्त्री के पांच चरणों में तृतीय चरण में 04 राजमिस्त्री महिला, चतुर्थ चरण में 14 महिलाये, पांचवे चरण में 20 महिलाये कुल 38 महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण सफल हुई प्रशिक्षण के पूर्व घर से बाहर



राजमिस्त्री प्रशिक्षण लेना ग्रामीण क्षेत्र में कठिनाईयों का सबब है। महिलाओं को बहुत कठिनाईयां आईं, छोटे बच्चों को घर में छोड़ना, घरवालों की सहमति समाज के तानेबाने विरोध घर का काम करके बाहर जाकर कार्य करना फिर घर के काम करना लगभग एक से ढेर माह (45 दिन का प्रशिक्षण) कार्य करना एक चुनौती भरा कार्य था।



- महिला राजमिस्त्री श्रीमती संध्या गोहे का मानना है कि राजमिस्त्री का प्रशिक्षण के पूर्व महिलाओं से केवल मजदूरी का कार्य लिया जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्रारम्भ कर महिला-पुरुष के लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया आज मैं राजमिस्त्री का कार्य कर रहीं हूँ।
- श्रीमती किरण वाडेकर के घर में 04 सदस्य हैं पति का देहांत लम्बी बीमारी के कारण हो रोजी-रोटी को समस्या आन पड़ी ऐसे में क्यां करें क्यां ना करें। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में महिला राजमिस्त्री हेतु प्रशिक्षण की सहमति दी गयी और मेहनत कर के प्रशिक्षण प्राप्त आज मैं राजमिस्त्री का कार्य कर बच्चों का भरण पोषण कर रहीं हूँ।
- श्रीमती शारदाबाई, श्रीमती इमल कडवे, श्रीमती वंदना बुवाडे, श्रीमती अनिताबाई सभी का कहना है— घर में बैठने एवं घरेलू लड़ाई-झगड़े से बचकर कार्य करने का जरिया बना। राजमिस्त्री का कार्य एवं मजदूरी से मिली आमदनी घर को बेहतर बनाने में सहायक हुई आज हम सब लॉकडाउन में भी ग्राम पंचायत में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे हैं।

शासन जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं डेमोस्टर द्वारा दिये सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर, पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी कर कार्य कर रहे हैं, यह शासन का सफल प्रयास है। ऐसे ही प्रशिक्षण प्राप्त कर एवं कार्य कर के लैंगिक भेदभाव समाप्त किये जा सकते हैं।

सी.के. चौबे,  
संकाय सदस्य



## समूह से मिला रोजगार और बनी पहचान – सफलता की कहानी

ग्राम अगनुपुरा तेहसील गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश हमारे गांव में सी.आर.पी. दीदियों की टीम आई, उन्होंने समूह की जानकारी दी तो उनकी बात समझ कर मैंने समूह का गठन करवाया। दिनांक 12.12.2017 में गठन हुआ, उसके बाद खाता खुलवाया, फिर



उसके बाद आर.एफ. प्राप्त हुआ। एक दीदी ने दुकान के लिए सी.आई.एफ. राशि रु. 80,000 का लोन लिया। 20–20 हजार का लोन चार दीदियों ने लिया, उसमें से मैंने दो सिलाई मशीन ली और पीको मशीन उससे मैंने सिलाई के साथ फॉल, अस्तर, लैस, ब्लाउज डोरी की दुकान डाली जिससे मेरी इनकम बढ़ी। पहले मैं बेरोजगार थी अब हमारे जीवन में काफी बदलाव आया है और मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमीशन करवाया जिससे उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई।

आज की दिनांक में हमारी एक लड़की कॉलेज में पढ़ती है और मेरे समूह में बुक कीपर का कार्य करती हूं और समूह की दीदियों को ट्रेनिंग भी देती है उसका नाम वर्षा निगम है। पहले की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी अब बहुत अच्छी है इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे समूह में जुड़कर बहुत लाभ मिला।



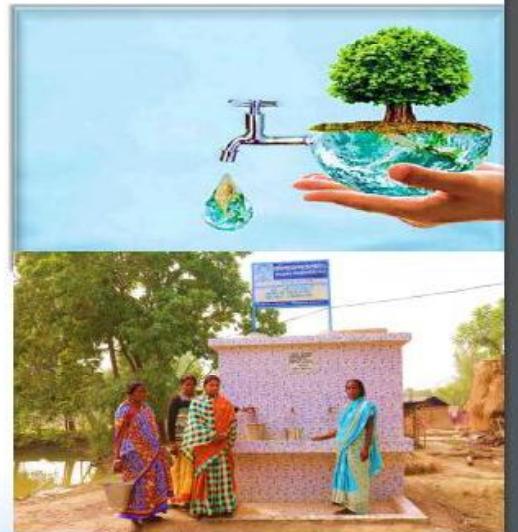
कृषि विभाग द्वारा रु. 20,000/- रुपये का इनाम मिला उससे मैंने तीन बकरी खरीदी इससे मुझे रु. 10,000/- का फायदा हुआ फिर मैंने रामदुलारी दीदी को बकरी वाला काम दे दिया। क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। इसलिए आशा करती हूं कि सभी दीदियों को बदलूंगी, सबको लाभ दिलाऊंगी।

आजीविका मिशन एवं सभी एन.आर.एल.एम. स्टाफ को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं जिसने मेरा दिशा परिवर्तन किया एवं आत्मनिर्भर बनया। इसी प्रकार अन्य महिलाएं जो गरीबी से ग्रसित हैं उनके लिए म.प्र. शासन की एस.आर.एल.एम. योजना वरदान साबित है, वह महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं साथ ही शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं।

शैलेन्द्र सिंह कुशवाहा,  
संकाय सदस्य



## जल की प्रचुरता वाला गांव



**विजन –** सभी के लिए कियाशील पाइप पेयजल कनेक्शन वाला गांव लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति अच्छे जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए प्रचूर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के परिस्थितिक तंत्र का सरक्षण।

**उद्देश्य –** सन 2024 तक ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को घर घर में नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं प्रर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया है।

जल मानव जीवन के लिए आवश्यक है, विभिन्न जल स्रोतों में वर्षा धाराओं, नदियों, झील, तालाब, खुले कुए़, बोरवेल, नलकुप आदि हर परिवार को पानी की जरूरत कई उद्देश्यों के लिए जैसे— खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, बर्टन धोने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए,

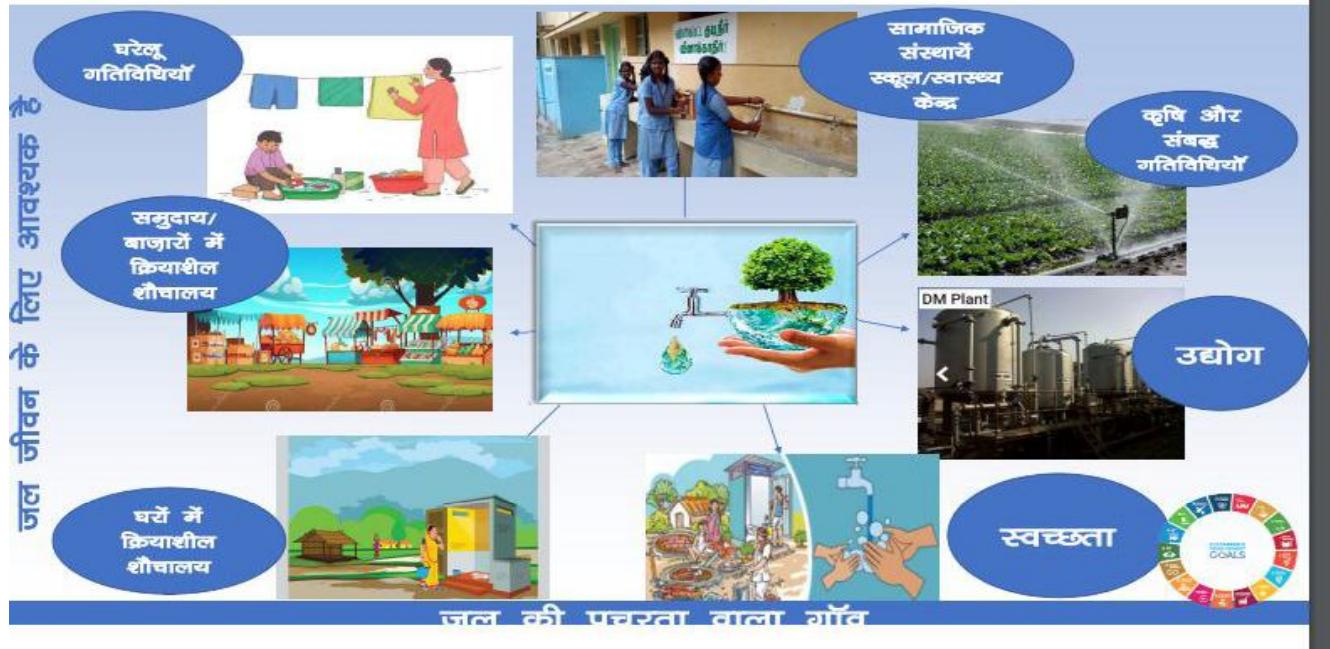
व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए, घरेलु जानवरों/पशुओं के लिए, घर के आस पास एवं चारों तरफ पौधों को पानी देना आदि उपयोग के लिए पानी की आवश्यकता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत



जल की प्रचुरता वाला गांव





एवं अन्य इमारत और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है उद्योग और अन्य प्रतिष्ठान प्रत्येक उद्देश्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त गुणवत्ता का पानी सुनिश्चित करना चुनौती है ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

स्वच्छता का सीधा संबंध पानी की उपलब्धता से है। घरेलू स्तर पर सामुदायिक स्तर पर, बाजारों में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्यात्मक शौचालयों को साफ और स्वच्छ तरीके से रखरखाव को सक्षमकरने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।

कुछ ग्राम पंचायत स्वाभाविक रूप से पानी और अच्छी वर्षा से सम्पन्न होते हैं ताकि पानी की उपलब्धता और निकासी को संतुलित किया जा सके हलाकि कई और लोगों को पानी के गिरते स्तर और घरेलू और कृषि की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ता है, विशेष रूप से खराब वर्षा के वर्षों में गंभीर चिन्ता का विषय जल निकायों का लुप्त होना और प्राकृतिक ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के साथ हस्ताक्षेप और अधिक दोहन है। यह मानते हुए यह लोगों और घर के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित है। कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्त्रोत स्थिरता उपायों को भी लागु करेगा, जैसे की भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग।

सज्जन सिंह चौहान,  
संकाय सदस्य

